[The Vice-Chairman, (Shri Triloki Nath Chaturvedi), in the Chair.]

have been feeling that somehow or the other the investigative agencies are perhaps not doing what is expected from them. In the Hawala case, there was so much of drum beating, so much of talk, so much of discussion in the last three or four years. Now we find that the whole case has been put into a shambles. The chargesheets have not been properly prepared and the court is saying that they will not be going by only one documentary evidence, there is not enough of corroborative evidence. If this is the state of investigation, how can you go to find out what is acutally happening, how can you bring the criminals to book?

On Bofors, I think, we had given a promise that sometime in April or May, the report would be given to the nation about the present state of the case. Now, it is July. A lot of material has arrived from Geneva. The boxes had been shown by the delegation. We all know a lot of material is there, lots of issues are to be resolved. We were told that within one month somebody in the CBI would go through it and would come out with a report and perhaps we will be able to name them. Unfortunately so far we have not received any report from CBI. The Director of CBI himself has been transfered. In such a situation, all the investigations have really been reduced to nothing. Nothing much is coming out. I am also worried not only about corruption, but also about all kinds of cover-ups. We have seen a recent case where a Chief Minister has been replaced by his wife who will be sitting there working in that seat until the same old man comes back. If this is the way the things are functioning, how could we have any respect for justice, respect for investigation and the agencies which are conducting them? What I am suggesting is that there has to be a proper thinking on the part of the Government to come out with clear assurance that important issues like the Hawala, Bofors, would be periodically discussed and the report would be given to the Parliament so that every three months or four months we know the present status of the case and we in Parliament are in a position to raise these issues which would be in the public interest. Thank you.

RE: DEMORALISATION OF PUNJAB STATE POLICE AND REVIVAL OF MILITANCY IN PUNJAB

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): वाइस चेयरमैन साहब, श्री इन्द्र कुमार गुजराल हमारे प्रधान मंत्री जी ने पंजाब का 8500 करोड़ रुपये का कर्जा पिछले दिनों मुआफ किया था और उन्होंने इस मौके पर कहा था कि, क्योंकि पंजाब ने देश की अखंडता की लड़ाई लड़ी थी इसलिए इस बोझे को पंजाब क्यों उठाए, सारा देश उठायेगा। हम उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया लेकिन पंजाब में जिन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अपनी जानें कुर्बान की थीं, आज वे बड़े डीमोरेलाइज्ड पोज़ीशन में है। पंजाब में 30 हजार लोग आतंकवाद की नज़र हुए। 18,000 पुलिस वाले अपनी फैमिलीज़ के साथ कुर्बान हुए और जब पंजाब में अमन आया, हिन्दुस्तान की अखंडता की लड़ाई लोगों ने लड़ कर जीत ली तो ऐसी डीमोरेलाइज़ेशन लोगों में आई कि उसकी एक निशानी तरनतारन के एस० एस० पी० अजीत सिंह सिद्धू ने खुदकशी करके जलील होने की बजाय, ह्यूमिलिएट होने की बजाय जेल में उन टैरोरिस्टों के साथ रहने की बजाय जिनके साथ उन्होंने लड़ाई की थी, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करना बेहतर समझा। मुझे अजीत सिंह सिद्धू के बारे में कोई उनकी वकालत नहीं करनी। लेकिन जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं, जो कौमें उन लोगों को भूल जाती हैं जो दूसरों के लिए जाने कुर्बान करते है और अपने देश के लिए लड़ते हैं तो फिर कौन मुश्किल वक्त में किसी दूसरे आदमी के लिए लड़ेगा और देश के लिए अपनी कुर्बानी देगा? उस वक्त पंजाब के जो हालात थे हो सकता है उन पुलिस आफिसर्स ने ऐसे मीन्ज़ अख्तियार किए हों जो पुलिस के संतुलन में शायद न हों, लेकिन जिस हालात में उन्होंने वह लड़ाई लड़ी उसको आपको याद रखना चाहिए। पंजाब में उस वक्त टैरोरिज़्म का एब्सोल्यूटली राज था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कोलैप्स हो चुकी थी, जुडीशियरी अपने फरायज़ को सरअंजाम देने में कतई तौर पर नाकाम हो चुकी थी। पैरेलल आर्मी अलैक्वाडिनों की

डिक्टेट से अपने मज़मून और खबरें लिखा करते थे और जो अखबार वाला उनके इशारे पर नहीं चलता था उनको लाला जगत नारायण की तरह और रमेश चन्द्र की तरह गोलियों से उड़ा कर उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता था। उस वक्त देश में पाकिस्तान की तरफ से टैरोरिज़्म फैला कर लो इंटेंसिटी वार को जारी करके, प्रोक्सी वार को जारी करके एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। उस वॉर लाइक सिचुएशन में गलतियां भी हो सकती हैं, एक्सैसेज़ भी हो सकती हैं, लेकिन किसी आदमी को बुरा कहने से पहले, उनको सज़ा देने से पहले, उनको ह्यूमिलिएट करने से पहले इस बात को देखना चाहिए कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी देश के लिए, देश के लोगों के लिए, पंजाब को आतंकवाद से छुटकारा दिलाने के लिए लड़ी। उसकी बैकग्राउंड क्या थी। यह सब देख कर तब उनकी किस्मत का फैसला करना चाहिए। तरनतारन उस वक्त टैरोरिज़्म का एक गढ़ था और आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि झुंड के झुंड...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप समाप्त कीजिए, आपने अपना प्वायंट् मेड कर दिया।

श्री वीरेन्द्र कटारिया: देखिए बस दो मिनट, मैं आपसे यह चाहता हूं कि उस वक्त तरनतारन आतंकवाद का गढ़ था और अगर तरनतारन पंजाब के हाथ से निकल जाता तो पंजाब का हिन्दुस्तान से निकलना इनएवीटेबल था और उसके बाद काश्मीर का भी यही हश्र होता। जिन लोगों ने इस बैकग्राउंड में प्रोक्सी वार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों को अगर आज हम डीमोरेलाइज़ कर देंगे तो वे हमारे मुश्किल वक्त में क्या काम आयेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस पुलिस फोर्स में डीमोरेलाइज़ेशन की वजह से आज पंजाब में पुलिस बहुत डीमोरेलाइज़ है और इसकी वजह से आज पंजाब में फिर आतंकवाद के वाकयात हो रहे हैं। आज पठानकोट में बम फटता है, भटिंडा की ट्रेन में बम फटता है, बाघापुराना में लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, फिरोजपुर में लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, मैं किसी सरकार को, आज की सरकार को दोष नहीं देना चाहता जो पंजाब की है, लेकिन यह कहे बगैर मैं नहीं रह सकता कि जो डीमोरेलाइजेशन पंजाब की पुलिस में आई है उसका यह डाइरेक्ट नतीजा है कि...। पंजाब के अंदर फिर से मिलिटेंसी रिवाइव होने की बात हो रही है। मैं आप के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लॉ को अमेंड किया जाए। जो लोग करप्ट हैं, जिन लोगों ने ज्यादतियां की है, उन को सजा दी जाए। ऐसे भी लोग थे जो कि 10 साल जब आतंकवाद चल रहा था तो कभी नजर नहीं आए। लोग मर रहे थे और वह अपने एअर कंडीशंड ड्राइंग रूम में बैठकर इंटैलेक्चुअल बातें करते थे जबकि लोग गोलियों का शिकार हो रहे थे। जिन लोगों ने उस वक्त लोगों की मदद की, उनको जब आतंकवाद की जंग में वे हार गए तो सिविल ह्यूमन राइट्स का बहाना बनाकर आज निशाना बनाया जा रहा है। तो देश को इस बात को बर्दास्त नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन को देखकर उन की मदद करने के लिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे बहादुर लोगों की मदद करने के लिए लॉ को अमेंड कर के कोई-न-कोई तरीका निकालना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आतंकवाद में हिस्सा लिया, आज पंजाब में कुछ लोगों को कारपोरेशन का चेयरमेन बनाने की बात चल रही है। ...(**व्यवधान**)...

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पंजाब के बारे में चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब के ऊपर 17500 करोड़ रुपये का कर्जा है। पंजाब के ऊपर इतना कर्जा क्यों है, इसका कारण यह है कि पंजाब में आतंकवाद के समय में पंजाब के किसानों ने अपने ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली का कनैक्शन नहीं लिया। उस समय पंजाब के किसानों ने अपने ट्यूबवैल चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया। उस समय पंजाब के किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी गई। उस समय पंजाब के किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने के कारण पंजाब के ऊपर 17500 करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले दिनों इस बात को साफ किया था और उन्होंने इस मौके पर कहा था कि क्योंकि पंजाब ने देश की आतंकवाद की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इस बोझ को पंजाब क्यों उठाए, सारा देश उठाएगा। हम इसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन पंजाब में जिन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अपनी जानें कुर्बान की थीं, आज वे बड़े "डिसीलूशन" पोजीशन में हैं। पंजाब में 30 हजार लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। 18000

کو پسند ہو چکی تھی جو ڈیوٹی اپنے فرائض کو سرانجام دینے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ پریس والے آتنکوادیوں کی ایجنسیوں سے اپنے مضمون اور خبریں لکھا کرتے تھے۔

اور جو اخبار والا ان کے اشارے پر نہیں چلتا تھا انکو لالہ جگت نرائن کی طرح اور رمیش چندر کی طرح گولیوں سے اڑا کر انکی آواز کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اسوقت دیش میں پاکستان کی طرف سے ٹیرورزم پھیلا کر "نو انٹیفیدیڈ وار" کو جاری کرکے "پروکسی وار" کو جاری کرکے ایک "نو ونر لائن سچوایشن" تھی۔ اس وار لائن سچوایشن میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ "ایکسیسز" بھی ہو سکتی ہیں لیکن کسی آدمی کو سزا دینے سے پہلے اسکو سزا دینے سے پہلے تو "شو میوٹ" کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ انھوں نے جو لڑائی لڑی دیش کیلئے۔ دیش کے لوگوں کیلئے۔ پنجاب کے آتنکواد سے چھٹکارا دلانے کیلئے لڑی۔ اسکی "بیک گراؤنڈ" کیا تھی یہ سب دیکھکر تب انکی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہیے "ٹرن تارن" اسوقت ٹیرورزم کا ایک گڑھ تھا۔ اور آپکو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کے جھنڈ کے جھنڈ ... "مدراخلت" ...

اب ادھیکش "شری تروی ناتھ چترویدی"

پولیس والے اپنی قیمتی جانیں کے ساتھ قربان ہوئے اور جب پنجاب میں امن آیا بھارت کا انھوں تانی لڑائی لوگوں نے لڑکر جیت لی تو ایسی "ڈرامو لائزیشن" لوگوں میں آئی کہ اسکی ایک نشانی "ٹرن تارن" کے ایس ایس پی

اجیت سنگھ سندھو نے خودکشی کرکے ذلیل ہونے کے بجائے "شو میوٹ" ہونے کے بجائے جیل میں ان ٹیرورسٹوں کے ساتھ رہنے کے بجائے جنکے ساتھ انھوں نے لڑائی لڑی تھی انھوں نے اپنی جان کو قربان کرنا بہتر سمجھا۔ مجھے اجیت سنگھ سندھو کے بارے میں کوئی انکی وکالت نہیں کرنی لیکن جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں۔ جو قومیں ان لوگوں کو بھول جاتی ہیں جو دوسروں کیلئے جانیں قربان کرتے ہیں اور اپنے دیش کیلئے لڑتے ہیں تو پھر کون مشکل وقت میں کسی دوسرے آدمی کے لئے لڑے گا۔ اور دیش کیلئے اپنی قربانی دے گا۔ اس وقت پنجاب کے جو حالات تھے ہو سکتا ہے ان پولیس افسروں نے "پیسٹ میتھڈز" اختیار کئے ہوں جو پولیس کے "منیوول" میں نہ ہوں لیکن جن حالات میں انھوں نے وہ لڑائی لڑی اسکو آپکو یاد رکھنا چاہیے۔ پنجاب میں اسوقت "ٹیرورزم" کا "البسولیوٹ" راج تھا۔ سیول ایڈمنسٹریشن کو مکمل

پنجاب کے اندر پھر سے ملیٹینسی ریوائو ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ میں کونسے ماڈیم سے ہندوستان کی سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاء اینڈ آرڈر مینٹیننس کیا جائے جو لوگ کرپٹ ہیں۔ جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں انکو سزا دی جائے۔ ایسے بھی لوگ تھے جبکہ دس سال جب آتنکواد چل رہا تھا تو لکھی نشر نہیں آئے۔ لوگ مر رہے تھے اور وہ اپنے "ایئر کنڈیشننگ ڈرائنگ روم" میں بیٹھ کر انٹیلیکچول باتیں کرتے تھے۔ جبکہ لوگ گولیوں کا شکار ہو رہے تھے جن لوگوں نے اسوقت لوگوں کی مدد کی انکو جب آتنکواد کی جنگ میں وہ ہار گئے تو سول لبرٹیز کا بہانہ بنا کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دیش کو اس بات کو برداشت نہیں کرنا چاہیئے۔ اس سچویشن کو دیکھکر انکی مدد کرنے کیلئے میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہادر لوگوں کی مدد کرنے کے لئے لاء اینڈ آرڈر مینٹیننس کرنے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیئے۔

میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آتنک واد میں حصہ لیا۔ آج پنجاب میں کچھ لوگوں کو کارپوریشن کا چیئرمین بنانے کی بات چل رہی ہے۔]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think you have made your point very

اب آپ سماپت کیجیئے۔ آپنے اپنا پوائنٹ "میڈ" کر دیا۔

شری ویر پرتاپ کمار: دیکھئے بس دو منٹ۔ میں آپسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسوقت ترن تارن آتنکواد کا گڑھ تھا اور اگر ترن تارن پنجاب کے ہاتھ سے نکل جاتا تو پنجاب کا ہندوستان سے نکلنا "ان ایوی ٹیبل" تھا اور اسکے بعد کشمیر کا بھی یہی حشر ہوتا۔ جن لوگوں نے اس بیڈ گراؤنڈ میں "ہیومن رائٹس" کے خلاف لڑائی لڑی حق ان لوگوں کو اگر آج ہم "ڈی موریلائز" کر دینگے تو وہ ہمارے مشکل وقت میں کیا کام آئینگے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پولیس فورس میں "ڈی موریلائزیشن" کی وجہ سے آج پنجاب میں پولیس بہت "ڈی موریلائز" ہے اور اسی وجہ سے آج پنجاب میں پھر آتنک کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج "پٹھان کوٹ" میں بم پھٹتا ہے۔ بھٹنڈا کی ٹرین میں بم پھٹتا ہے وہ جگہ پرانا میں لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ فیروزپور میں لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ میں کسی سرکار کو دوش نہیں دینا چاہتا جو پنجاب کی ہے۔ لیکن یہ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ جو ڈی موریلائزیشن پنجاب پولیس میں آئی ہے اسکا یہ ڈائرکٹ نتیجہ ہے کہ

effectively. We should not go into other matters. You have drawn attention to the issue. We should not go into the question of who is being appointed or who is not. ...(*Interruptions*)... You are a very senior Member. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA KATARIA: I would conclude by saying that we should not forget those people who have sacrified their lives, lives of their family members and those who performed and discharged their lawful duty. They have fought a war of our country. This is of paramount importance that they were not fighting just to restore peace in Tarantarn or in the State as a whole, but they were fighting a war for the country. So, we must see it in that perspective and try to save our brave people. Otherwise, the nations who forget their heroes, they do not find any place in the history of the world. They go into the abysmal depth of history. I again request that the nation should take care of them. Thank you.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (Delhi): Sir, I just to associate myself with the sentiments expressed by the hon. Member. ...(*Interruptions*)... महोदय, मैं सिर्फ एसोशिएट करना चाहता हूं। महोदय पंजाब में फिर से आतंकवाद आ रहा है तब पुलिस को डिमोरेलाइज नहीं करना चाहिए। जहां एक भी आतंकवादी को सजा नहीं हुई और हजारों पुलिस वाले जेल में हैं। महोदय, मैं वीरेन्द्र कटारिया जी के साथ अपने को एसोशिएट करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): धन्यवाद।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): सर, ऑनरेबल मेंबर जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी है उनको चैयरमेन लगाया जा रहा है। अगर आप के पास किसी का नाम है कि किस को लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है ...(**व्यवधान**)...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (Delhi): You should not take up this case like this. ...(*Interruptions*)... You are a Minister. ...*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अगर वह होगा तो वह सरकार को भी इत्तला करेंगे। जनता को भी इत्तला करेंगे। ऐसी चीजें कोई पर्दे के पीछे तो नहीं हुआ करती हैं।

RE. UNDUE RESTRICTIONS BY THE WEST ON INDIA'S TRADE

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Sir, our country is saturated with problems—political, administrative, social, economic and ethical. In spite of our differences in perception, all of us have been grappling with those problems inside the country. Sir, we are facing problems created not only by our hostile neighbours but we are also facing problems created by those countries which are supposed to be our friends, which are supposed to be our benefactors and which are supposed to be our global partners. Today this is the subject of my submission.

Sir, we are pound of our achievements and we are proud of our scientists who have made our achievements possible in space technology and in nuclear and missile programmes. Let us recall the treacherous embargo on our acquiring croygenic engine from Russia for our space programme. It was intended to cap our Prithvi programme and stall our Agni launching though both are supposed to vegetarians!...In a sense they are not very harmful when compared to our neighbour's missile. In 1980's the U.S. did not permit the sale of its advanced CRAY-X super computer to India for use in weather forecast. Our scientists have taken up the challenge and made the Cryogenic Engine and the Super Computer. The same is the story about the nuclear power plants also. During the last few weeks, restrictions were placed on American Exports to Indian companies—both private and public—on the plea that they are supporting nuclear proliferation activities in India. The companies include both private and public sector companies-